बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 103 ● नई दिल्ली ● शनिवार 31 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली उच्च न्यायालय में दो मिनट का मौन रखा गया

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की स्मृति में शुक्रवार को दो मिनट का मौन रखा। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय की अदालत में 'कोर्ट मास्टर' ने कहा, ''सभी से अनुरोध है कि भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वालों की स्मृति में कृपया खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।'' अदालत में मौजूद सभी लोगों ने पूर्वाह्न 11 बजे मौन रखा और कोर्ट मास्टर द्वारा मौन समाप्त करने की घोषणा किए जाने तक कार्यवाही स्थगित रही। 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा बजट, सीनियर पार्षद ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली । दिल्ली नगर निगम के आगामी वित्त वर्ष के बजट को लेकर निगम सदन में सियासत गरमा गई है. स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्या शर्मा द्वारा पेश बजट पर एक ओर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है तो वहीं सत्तापक्ष इसे ऐतिहासिक और विकासोन्मुखी बता रहा है. बजट ने निगम की राजनीति को दो साफ ध्रुवों में बांट दिया है. इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेता और वरिष्ठ निगम पार्षद मुकेश गोयल ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के बजट को खोखले वादों का पुलिंदा करार दिया है. उन्होंने कहा कि आप ने बीते तीन वर्षों में एमसीडी को पीछे की ओर धकेलने का काम किया है. अब जो बजट पेश किया गया है, वह 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' जैसा है. मुकेश गोयल ने कहा कि बजट में पार्षद फंड को 1 करोड़ 55 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह अतिरिक्त राशि कहां से आएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना आय बढ़ाए किसी भी मद में खर्च संभव नहीं है. पिछले वित्त वर्ष में पार्षद फंड से केवल 25 लाख रुपये ही जारी किए गए, जबकि बड़ी राशि अब भी बकाया है. पहले पुराने फंड का भुगतान करने के बजाय नए फंड की घोषणा करना केवल दिखावा है. कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के मुद्दे पर मुकेश गोयल ने कहा कि एमसीडी में वर्ष 2016-17 के बाद कोई नई कच्ची भर्ती नहीं हुई है. यदि सत्ताधारी दल कर्मचारियों के हित में ईमानदार है तो सभी विभागों के कर्मचारियों को पक्का

करने के लिए ठोस प्रस्ताव लाना चाहिए. बजट में इसके लिए कोई स्पष्ट बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है. बिना फंड की व्यवस्था के कर्मचारियों को पक्का करना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी भर्ती नियमों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते हैं. उनके लिए 'वन टाइम रिलेक्सेशन' की योजना लाई जानी चाहिए. ऐसा पहले भी किया जा चुका है. उन्होंने दो टूक कहा कि मौजूदा बजट प्रस्ताव अव्यवहारिक और खोखले हैं, जिन्हें जमीन पर उतारना नामुमकिन है. दूसरी ओर, दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा द्वारा पेश बजट को सत्तापक्ष का पूरा समर्थन मिला है. नेता सदन प्रवेश वाही ने इसे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप और विकास को गति देने वाला बताया है.

प्रवेश वाही ने कहा कि यह संभवतः एमसीडी का पहला लाभ वाला बजट है. संपत्ति कर संग्रह मजबूत करने, पार्किंग व्यवस्था के विस्तार, विज्ञापन नीति में पारदर्शिता और साप्ताहिक बाजारों के नियमितीकरण से निगम की आय बढ़ेगी. नेता सदन के अनुसार बजट में वायु प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और हरियाली बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. एमसीडी स्कूलों में स्मार्ट सुविधाएं और हर वार्ड में आयुष्मान आरोग्य मंदिर व स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव को उन्होंने अहम बताया. प्रवेश वाही ने कहा कि निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण, पदोन्नति और नई भर्तियों पर भी फोकस किया गया है.

महिला सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, सोलर ऊर्जा, ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट सुविधाएं दिल्ली को आधुनिक शहर बनाने में सहायक होंगी.

बहरहाल, एमसीडी बजट को लेकर एक ओर जहां विपक्ष इसे खोखला और अव्यवहारिक बता रहा है. वहीं सत्तापक्ष इसे विकास और आत्मनिर्भरता का मजबूत दस्तावेज मान रहा है. अब असली परीक्षा बजट के क्रियान्वयन की होगी, जो तय करेगी कि यह घोषणाओं का पुलिंदा साबित होता है या दिल्ली को नई रफ्तार देने वाला रोडमैप है.

कांग्रेस का दिल्ली में वीबी-जी राम-जी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गांधी स्मृति की ओर जाने से रोका

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बदलकर लाए गए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025 के खिलाफ मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान तेज कर दिया है। 30 जनवरी को दिल्ली में पार्टी के प्रमुख नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। बता दें कि अकबर रोड स्थित एआईसीसी मुख्यालय के बाहर मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा के दौरान दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। वे 30 जनवरी रोड से गांधी स्मृति की ओर जा रहे थे। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा, सांसद जयराम रमेश और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नई दिल्ली में प्रदर्शन किया।

पवन खेड़ा ने कहा, जो सरकार मजदूर और किसान का अपमान करती है, वह लंबे समय तक नहीं टिकती। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों की राजधानियों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहा, मनरेगा बचाना मतलब मजदूर की आवाज बचाना है। इस देश में मजदूर और किसान का अपमान करने वाली कोई सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकी है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने से रोका। उन्होंने कहा, हम शांतिपूर्ण अभियान चला रहे थे, लेकिन हजारों पुलिसकर्मियों ने हमें रोक लिया। मैं मोदी सरकार को चेतावनी देता हूं कि वे हमारे संकल्प को नहीं तोड़ पाएंगे। केरल में AICC महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने केंद्र पर नागरिकों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, नए मनरेगा बिल से पहले रोजगार का अधिकार छीना गया। अब आर्थिक सर्वे में सूचना का अधिकार को बेकार बताया गया है। उनका इरादा साफ है कि सामान्य नागरिकों के सभी अधिकार छीनना चाहते हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यूनियन बजट 2026 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार लोगों को अपनी कृपा से सब कुछ दे रही है।कांग्रेस का मुख्य विरोध इस बात पर है कि नए कानून में महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, केंद्र-राज्य फंड शेयरिंग 60:40 कर दी गई है (पहले केंद्र पूरी फंडिंग करता था), और योजना को पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में लाया गया है। हालांकि, नए एक्ट में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों की गई है।यह प्रदर्शन मनरेगा बचाओ संग्रा% अभियान का हिस्सा है, जो 10 जनवरी से शुरू हुआ और 25 फरवरी तक चलेगा। कांग्रेस ने मनरेगा को मूल रूप में बहाल करने और नए कानून को वापस लेने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यह ग्रामीण मजदूरों के संवैधानिक अधिकार पर हमला है।

अंगूर खट्टे हैं, जयराम रमेश पर पीयूष गोयल का तंज, पूछा- चीन को क्यों पहुंचा रहे थे फायदा?

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को लेकर कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की, खासकर चीन के साथ हुए समझौतों को लेकर। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर जयराम रमेश के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए गोयल ने उनकी प्रतिक्रिया को अंगूर खट्टे हैं कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी 2006 में चर्चा शुरू करने और 2007 में इसे आगे बढ़ने के बावजूद समझौते को अंतिम रूप देने में विफल रही। गोयल ने रमेश की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें विकास-विरोधी माना जाता है और पर्यावरण मंत्री के रूप में उन्होंने देश के विकास पथ को अवरुद्ध किया है। मंत्री गोयल ने कांग्रेस पार्टी से अपने कार्यों का हिसाब मांगा और पूछा कि चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर विचार करके उन्होंने भारत के हितों को कैसे खतरे में डाला। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी ने भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में शामिल होने की अनुमति कैसे दी, जो असल में चीन और भारत के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता था। एएनआई से बात करते हुए गोयल ने कहा, ये तो अंगूर खाते हैं वाली कहानी है। 2006 में बातचीत शुरू हुई, 2007 में आगे बढ़ी और 2013 में बंद हो गई। उनमें समझौते को अंतिम रूप देने का साहस या इच्छाशक्ति तक नहीं थी। डर के मारे यूपीए और कांग्रेस सरकारें कभी कोई निर्णायक कदम नहीं उठा सकीं। और जयराम रमेश को तो विकास विरोधी माना जाता है, ये तो आप देख ही चुके हैं। पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने देश के विकास की राह रोक दी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड इतना खराब है। जयराम रमेश जैसे दोस्त और कांग्रेस जैसी पार्टियां भारत को चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में शामिल होने के लिए उकसा रही थीं। मैं उनसे सीधे पूछना चाहता हूं आपने भारत को आरसीईपी में शामिल होने देने के बारे में सोचा भी कैसे, जो असल में चीन और भारत के बीच एक एफटीए था? आपने भारत को खतरे में डालने का साहस कैसे किया? ये कांग्रेस की एक गंभीर गलती थी। कांग्रेस को जनता को जवाब देना होगा कि वे चीन के साथ एफटीए के जरिए भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे तैयार हो गईं। ये है कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड।

संघ-हिंदू महासभा पर नजर रख रहे थे नेहरू और पटेल, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बोले जयराम रमेश

नई दिल्ली । शुक्रवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने वर्ष 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल के दो पत्र सार्वजनिक किए। इन दोनों ही पत्रों में दोनों दिग्गज नेताओं ने हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों की कड़ी आलोचना की गई थी। दोनों नेताओं के पत्र को सार्वजनिक करते हुए जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महात्मा गांधी की हत्या से दो दिन पहले जवाहरलाल नेहरू ने मुखर्जी को पत्र लिखा था, जबकि कुछ महीने बाद 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने भी उन्हें पत्र भेजा था। दोनों पत्रों में स्वयं को राष्ट्रवाद का संरक्षक बताने वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया गया था। इस दौरान जयराम रमेश ने 30 जनवरी 1948 की रात महात्मा गांधी की हत्या के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर दिए गए जवाहरलाल नेहरू के संबोधन का लिंक भी शेयर किया। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में यह लिखा कि नेहरू ने मुखर्जी को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि हिंदू महासभा ने पुणे, अहमदनगर और दिल्ली में प्रतिबंध आदेशों की अवहेलना करते हुए बैठकें की थीं। इन बैठकों के दौरान कुछ भाषणों में महात्मा गांधी को देश के लिए बाधा बताया गया और उनके शीघ्र निधन की बात कही गई थी।

सिख गुरु विवाद : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष का आरोप, पंजाब सरकार फाइल रोक रही; साजिश कर तथ्यों को छिपाने का शक

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने सिख गुरुओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में राय पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर से संबंधित फाइल को रोक रखा है। अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। विजेंद्र गुप्ता ने पत्रकारों से कहा कि विधानसभा सिख गुरुओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगी और सचाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा सिख गुरुओं के कथित अपमान को लेकर पंजाब सरकार के रवैये पर गहरी चिंता जताई। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संबंधित फाइल को लगातार रोके रखना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अब तक न तो एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई गई है, न ही शिकायत साझा की गई है और न ही कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति किसी साजिश की ओर इशारा करती है। इस मामले में चुप्पी और बार-बार हो रही देरी तथ्यों को छिपाने की जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाती है। इस केस के तार सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री तक जाते प्रतीत होते हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति छह जनवरी को हुई उस कथित घटना की जांच कर रही है, जो गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर हुई चर्चा के दौरान सामने आई थी। आतिशी ने समिति को दिए अपने जवाब में आरोपों को खारिज करते हुए उस दिन की विधानसभा कार्यवाही का बिना संपादन वाला वीडियो रिकॉर्ड मांगा है। गुप्ता ने दोहराया कि दिल्ली विधानसभा इस मामले को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेगी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक प्रशासनिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह गुरुओं के सम्मान, गरिमा और आस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इतने संवेदनशील मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या असंवेदनशीलता पूरी तरह अस्वीकार्य है। भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कथित वीडियो के आधार पर पंजाब पुलिस ने जालंधर में एफआईआर दर्ज की थी।

माखनलाल ने देखा था पत्रकारिता विश्वविद्यालय का सपना

जनसंचार और पत्रकारिता की शिक्षा आज एक विशिष्ट अनुशासन बन चुकी है। देश में पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा पर केंद्रित चार विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने ही सबसे पहले पत्रकारिता विद्यापीठ (विश्वविद्यालय) का सपना देखा था। उन्होंने भरतपुर(राजस्थान) में 1927 में आयोजित संपादक सम्मेलन में कहा था-हिंदी समाचार पत्रों के कार्यालय में योग्य व्यक्तियों के प्रवेश करने के लिए, एक पाठशाला आजकल के नए-नामों की बाढ़ में से कोई शब्द चुनिए तो कहिए कि एक संपादन कला के विद्यापीठ की आवश्यकता है। ऐसी विद्यापीठ जिसमें योग्य स्थान पर बुद्धिमान, परिश्रमी, अनुभवी, संपादन-शिक्षकों द्वारा संचालित होना चाहिए। उक्त पीठ में अत्यन्त विषयों का एक प्रकांड शब्द सहपाठन होना चाहिए। यह संयोग ही है कि उनके इस स्वप्न को 1990 में मध्यप्रदेश सरकार ने साकार करते हुए उनके नाम पर ही भोपाल में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद के दिनों में रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय और जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके साथ ही दो साल पूर्व भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। यह बात बताती है कि हमारे पुरखे किस तरह अपनी विधा को अकादमिक रूप से स्थापित होते देखना चाहते थे। माखनलाल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक, स्वतंत्रता सेनानी अनेक भूमिकाओं में सामने आते हैं। वे अप्रतिम वक्ता भी थे। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा-हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना (भाषण) तो माखनलाल जी ही जानते हैं। इतना ही नहीं राष्ट्रपिता ने कहा- मैं बाबई जैसे छोटे स्थान पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वह माखनलालजी का जन्मस्थान है। जिस भूमि ने माखनलालजी को जन्म दिया, उसी भूमि को मैं सम्मान देना चाहता हूं। यह संयोग ही है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और माखनलाल जी पुण्यतिथि एक ही दिन 30 जनवरी को मनाई जाती है। चर्चित शायर श्री फिराक गोरखपुरी भी माखनलाल जी कलम के प्रशंसक थे। उनका कहना था कि- उनके लेखों को पढ़ने से ऐसा मालूम होता था कि आदि-शक्ति शब्दों के रूप में अवतरित हो रही है या गंगा स्वर्ग से उतर रही है। यह शैली हिंदी में तो नहीं, भारत की दूसरी भाषाओं में भी विरले ही लोगों को नसीब हुई है। मुझ जैसे हजारों लोगों ने अपनी भाषा और लिखने की कला माखनलाल जी से ही सीखी। पं. माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में निकला 'कर्मवीर' एक ऐसा पत्र है, जिसकी धमक हम आज भी महसूस करते हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में 'कर्मवीर' एक ऐसा नाम है, जिसे छोड़कर भारतीय पत्रकारिता का समग्र मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसी तरह उसके संपादक पं. माखनलाल चतुर्वेदी और उनकी संपूर्ण जीवनयात्रा, आत्मसमर्पण के खिलाफ लड़ने वाले संपादक की यात्रा है। वस्तुतः वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे थे और कोई मोर्चा ऐसा न था, जहां उन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो। सही मायने में 'कर्मवीर' के संपादक ने अपने पत्र के नाम को सार्थक किया और माखनलाल जी स्वयं कर्मवीर बन गए। 4 अप्रैल, 1889 को होशंगाबाद(मप्र) के बाबई जिले में जन्मे माखनलालजी ने जब पत्रकारिता शुरू की तो सारे देश में स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव दिख रहा था। राष्ट्रीयता एवं समाज सुधार की चर्चाएं और फिरंगियों को देश बदर करने की भावनाएं बलवती थीं। इसी के साथ महात्मा गांधी जैसी तेजस्वी विभूति के आगमन ने सारे आंदोलन को एक नई ऊर्जा से भर दिया। दादा माखनलाल जी भी उन्हीं गांधी भक्तों की टोली में शामिल हो गए। गांधी के जीवन दर्शन से अनुप्राणित दादा ने रचना और कर्म के स्तर पर जिस तेजी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को ऊर्जा एवं गति दी वह महत्व का विषय है। इस दौर की पत्रकारिता भी कमोबेश गांधी के विचारों से खासी प्रभावित थी। हिंदी पत्रकारिता का वह जमाना ही अजीब था। आम कहावत थी - जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और सच में अखबार की ताकत का अहसास आजादी के दीवानों को हो गया था। इसी के चलते स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेताओं ने अपने पत्र निकाले। जिनके माध्यम से ऐसी जनचेतना पैदा की कि भारत आजादी की सांस ले सका। वस्तुतः इस दौर में अखबारों का इस्तेमाल एक अस्त्र के रूप में हो रहा था। माखनलाल जी ने 1913 में 'प्रभा' नाम की एक उच्चकोटि की पत्रिका के माध्यम से साहित्यिक पत्रकारिता में भी सार्थक हस्तक्षेप किया। लोगों को झकझोरने एवं जगानेवाली रचनाओं के प्रकाशन के माध्यम से 'प्रभा' हिंदी जगत का एक जरूरी नाम बन गयी। दादा की 56 सालों की ओजपूर्ण पत्रकारिता की यात्रा में प्रताप, प्रभा व कर्मवीर उनके विभिन्न पड़ाव रहे। साथ ही उनकी राजनीतिक वरीयता भी बहुत ऊंची थी। वे बड़े कवि थे, पत्रकार थे पर उनके इन रूपों पर राजनीति कभी हावी न हो पायी। इतना ही नहीं जब प्राथमिकताओं की बात आयी तो मप्र कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता होने के बावजूद उन्होंने सत्ता में पद लेने के बजाए मां सरस्वती की साधना को ही प्राथमिकता दी। आजादी के बाद 30 अप्रैल, 1968 तक वे जीवित रहे पर सत्ता का लोभ उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया। इतना ही नहीं 1967 में भारतीय संसद द्वारा राजभाषा विधेयक पारित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति को वह पद्मभूषण का अलंकरण भी लौटा दिया जो उन्हें 1963 में दिया गया था। वे समझौतों के खिलाफ लोगों में चेतना जगाते रहे। उन्होंने लिखा है-

अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली
यह सुधार-समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली।

'कर्मवीर' के संपादक कैसे संपादक थे, इसे बताने के लिए उन्होंने कहा कि हम फक्कड़ सपनों के स्वर्गों को लुटाने निकले हैं। किसी की फरमाइश पर जूते बनानेवाले चर्मकार नहीं हैं हम। यह निर्भीकता ही उनकी पत्रकारिता की भावभूमि का निर्माण करती थी। स्वाधीनता आंदोलन की आंच को तेज करने में उनका कर्मवीर अग्रणी बना।

कम ही लोग जानते होंगे कि दादा को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके संपादकीय कार्यालय यानी घर पर तिरसठ बार छापे पड़े, तलाशियां हुयीं। 12 बार वे जेल गए। कर्मवीर को अर्थाभाव में कई बार बंद होना पड़ा।

यू.जी.सी. इक्विटी रैगुलेशन : उलटी दिशा में सफर

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वीरवार यू.जी.सी. विनियम 2026 पर स्टे लगाने के बाद देश के हर सामान्य नागरिक विशेषकर छात्रों और शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। उसकी जगह कोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फिलहाल पूर्ववर्ती 2012 के नियम को लागू कर दिया है। मार्च के महीने में 2026 के विनियम पर विस्तृत सुनवाई होगी। लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने इसके बारे में जो टिप्पणियां की हैं, वे काफी गंभीर और विचारणीय हैं। उन्होंने जाति से जुड़े कुछ आधारभूत प्रश्न किए हैं। यू.जी.सी. के इस भेदभावपूर्ण विनियम के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े करती है।

खंडपीठ ने कहा कि हमें एक जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए लेकिन हम आजादी के 75 साल बाद भी जाति की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्या पिछले 75 वर्षों में हमने जो कुछ हासिल किया, उसको गंवाना चाहते हैं? यह चिंताजनक है। भारत का संविधान एक समावेशी समाज बनाने पर बल देता है। जातिवाद के खिलाफ हमने बड़े कदम उठाए हैं। जिस किसी को भी सुरक्षा की जरूरत है वह उसको मिलनी चाहिए। जहां तक इस विनियम का प्रश्न है, तो प्रथम दृष्टया यह अस्पष्ट दिखता है। कानून के विशेषज्ञों को इसकी भाषा को स्पष्ट करने की जरूरत है। अपने वर्तमान स्वरूप में इस विनियम के दुरुपयोग की संभावनाएं हैं और यह संविधान की धारा 31 सी को चुनौती देता है। ये वही प्रश्न थे जो हर किसी को खटक रहे थे। वास्तव में उच्च शिक्षा व्यवस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज को बांटने वाले पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर ज्ञान, विवेक और मुक्त चिन्तन को बढ़ावा दे। विश्वविद्यालय और कॉलेज विचारों के ऐसे मंच होते हैं, जहां व्यक्ति अपनी पहचान से पहले छात्र और फिर शोधकर्ता बनता है। दुर्भाग्यवश, यू.जी.सी. द्वारा प्रस्तावित इक्विटी रैगुलेशन 2026 इसी मूल भावना के विपरीत खड़ा दिखाई देता है।

यह विनियम समानता के नाम पर भेदभाव की एक ऐसी इकतरफा और संकीर्ण परिभाषा गढ़ता है, जो समस्या के समाधान से अधिक, नई समस्याओं को जन्म देने वाली है। स्वयं मेरे लिए एक शिक्षक के रूप में यह मानना कठिन है कि कक्षा में खड़ा होकर कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जाति के चश्मे से देखता या उनसे कोई भेदभाव करता है। वर्षों तक पढ़ाने, मार्गदर्शन देने और शोध कराने के दौरान एक शिक्षक के लिए छात्र की पहचान उसकी जिज्ञासा, अनुशासन और बौद्धिक क्षमता से बनती है, न कि किसी सामाजिक वर्ग से।

यही कारण है कि अधिकांश शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धियों में ईर्ष्या नहीं, बल्कि गर्व महसूस करते हैं, चाहे वे किसी भी जाति-वर्ग से हों। जिस रोहित वेमुला प्रकरण के आलोक में इस एकतरफा कानून को बनाने की बात कही जा रही थी, उसकी सच्चाई खुद तेलंगाना सरकार की रिपोर्ट में खुल चुकी है। यू.जी.सी. रैगुलेशन 2026 की सबसे गंभीर समस्या उसकी जातिगत भेदभाव की परिभाषा है। यह परिभाषा पहले ही यह मानकर चलती है कि शैक्षणिक परिसरों में भेदभाव एकतरफा होता है, यानी एक वर्ग स्वभावतः उत्पीड़क है और दूसरा पीड़ित। यह दृष्टिकोण न केवल बौद्धिक रूप से आलसी है, बल्कि सामाजिक रूप से खतरनाक भी। क्या भेदभाव केवल एक ही दिशा में होता है? क्या अपमान, बहिष्कार, वैचारिक उपहास और सामाजिक तिरस्कार किसी एक ही वर्ग तक ही सीमित है? आज का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग है। जिन्हें हम पिछड़ा या दलित कह कर संबोधित करते हैं, वे अब देश और समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उच्चतम पदों पर आसीन हैं और अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की अल्पसंख्यक सामान्य जाति की तरफ से इसका कोई विरोध भी नहीं है। फिर भी पिछले कुछ दशकों में विश्वविद्यालय परिसरों में खुलेआम जाति-आधारित नारेबाजी, सामूहिक अपमान और वैचारिक बहिष्कार के दृश्य देखे गए हैं। 'तिलक-तराजू और तलवार' जैसे प्रतीकों को गाली बनाकर प्रस्तुत करना, एक पूरे समुदाय को शोषक, मनुवादी या पितृसत्तात्मक कह कर खारिज करना अब फैशनेबल बना दिया गया है। संभवतः मार्च में जब इस विनियम पर सुनवाई होगी तो न्यायालय के समक्ष खतरनाक जातिगत भेदभाव के ये उदाहरण भी रखे जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए यदि अब सर्वोच्च न्यायालय की गंभीर टिप्पणियों को देखें तो यह स्पष्ट होगा कि हमारी असल जरूरत 'कास्ट-न्यूट्रल' कैंपस विकसित करने की है, जहां छात्र आपस में तथा छात्र और शिक्षक एक-दूसरे के साथ खुल कर बातचीत कर सकें और अपने विचार रख सकें।

सम्पादकीय...

दक्षिण एशिया की राजनीति का शिकार क्रिकेट

दक्षिण एशिया में राजनीतिक संकट ने न केवल शासन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि क्षेत्रीय खेल और सांस्कृतिक संबंधों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। यह स्थिति अब क्रिकेट, संगीत, नृत्य और कला आयोजनों तक फैल गई है जिससे आम जनता और खिलाड़ियों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह संकट विशेष चिंता का विषय है। खिलाड़ी मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय मैच और प्रशिक्षण कार्यक्रम बाधित हैं जिससे खेल के लिए इंटरनेशनल में देरी हो रही है। सांस्कृतिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। संगीत समारोहों, कला प्रदर्शनियों और पारंपरिक नृत्य कार्यक्रमों को रद्द या हटा दिया गया है। दक्षिण एशिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि राजनीति और कूटनीति का एक शक्तिशाली माध्यम है। भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों का सीधा असर द्विपक्षीय क्रिकेट पर पड़ता है। यह क्षेत्र विश्व क्रिकेट में सबसे प्रमुख है, जहां 'क्रिकेट कूटनीति' का उपयोग तनाव कम करने के लिए किया जाता है लेकिन अक्सर इसे राजनीतिक औजार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट कूटनीति में कई बार संबंधों में जमी बर्फ पिघलाने का काम किया है। क्रिकेट शांति का दूत बनने की क्षमता रखता है लेकिन यह राजनीतिक तनावों से अछूता है। मैच कभी-कभी देश के स्वाभिमान और कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक बन जाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उल-हक 1987 में जयपुर में होने वाले भारत-पाक क्रिकेट मैच देखने के लिए अचानक भारत आ गए थे। उसके बाद दोनों देशों में बातचीत शुरू हो गई थी। पाक प्रधानमंत्री यूसुफ गिलानी भी भारत आए थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति स्वर्गीय परवेज मुशर्रफ भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे महेन्द्र सिंह धोनी के लम्बे बालों के दिवाने रहे। बीसीसीआई द्वारा आईपीएल फ्रैंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश देने से शुरू हुआ मामला अब एक गंभीर संकट में बदल गया है। क्रिकेट के मैदान में खेल भावना के विपरीत एक तमाशा चल रहा है, जिसमें प्रतिबंध, अल्टीमेटम और टकराव की स्थिति शामिल है। दक्षिण एशिया में एक चिंताजनक परिवर्तन चल रहा है। यह सब दो ऐसे देशों और पड़ोसियों के बीच हो रहा है जिनके इतिहास और सांस्कृतिक संबंध आपस में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के लिए यह और भी आत्मघाती कदम साबित हो रहा है। खेल हमेशा राजनीति से अछूता नहीं रहता और यह सच है कि भारत-बांग्लादेश संबंध इस समय नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। फिर भी, आईसीसी के उस फरमान ने बांग्लादेश को आगामी टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया है और उससे पहले की घटनाओं से पता चलता है कि प्रतिक्रियावादी रवैया हावी हो गया है और दीर्घकालिक कूटनीति निष्क्रिय हो गई है। बांग्लादेश का रवैया प्रतिक्रियात्मक लगता है, न कि सक्रिय। चाहे यह उचित हो या नहीं, यह मुस्तफिजुर-आईपीएल घटना से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।

अजित पवार के बाद एनसीपी !

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया अजित पवार और चालक दल के सदस्यों समेत पांच लोगों की विमान दुर्घटना में मृत्यु दुखद है। अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए बारामती में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों की आंखों में आंसू दिखाई दिए। महाराष्ट्र में 6 बार उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार के राज्य में राजनीतिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अजित पवार जनता के नेता थे और जमीनी स्तर पर लोगों से उनका गहरा जुड़ाव था। उन्हें पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के वंचित वर्ग को सशक्त बनाने और समाज में हाशिये पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों के लिए याद किया जाता रहेगा। राजनीति तो दांव-पेंचों का ही खेल है और महाराष्ट्र की मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों में दांव-पेच कोई नई बात नहीं है। अजित पवार को महाराष्ट्र की सियासत में अपनी कलाबाजियों के लिए भी माहिर माना जाता था। उन्होंने अपने चाचा और दिग्गज मराठा नेता शरद पवार से ही सियासत के गुर सीखे। शरद पवार को वह अपना राजनीतिक गुरु कहते रहे लेकिन 2023 आने तक उन्होंने ऐसा दांव खेला कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने भाजपा को समर्थन दिया और स्वयं उपमुख्यमंत्री बन गए। वह पार्टी का चुनाव चिन्ह भी ले जाने में सफल रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे चाचा शरद पवार की छत्रछाया में 7 बार विधायक चुने गए। अलग राह चुनने के बावजूद चाचा शरद पवार के परिवार से उनके संबंध करीबी बने रहे। पारिवारिक समारोह में चाचा-भतीजा परिवारों को साथ-साथ देखकर इसका अनुमान लगाया जाना कठिन था कि सियासत में दोनों का रास्ता अलग-अलग है। यह वास्तविकता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं। यह वास्तविकता है कि राजनीति में कोई स्थायी नहीं होता और न ही स्थायी दुश्मन। अजित पवार अपनों के साथ भी रहे और धुर विरोधियों के साथ भी रहे। किसी दुर्घटना में हुई दुखद मृत्यु से राजनीति का चक्र बाधित नहीं होता लेकिन अजित पवार ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर थे कि उनकी मृत्यु ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इस दुख की घड़ी में यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा?

पिछले 10 वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति काफी संवेदनशील रही। एकमात्र प्रमुख ध्रुव के रूप में उभरने की कोशिशों में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को तो पराजित किया ही लेकिन शिवसेना और राकांपा में विद्रोह के बाद उभरे गुटों से भी समझौता किया। अजित पवार में एक कसक शुरू से ही रही कि 20 साल से अधिक समय से चाचा शरद पवार उनके मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में बाधा बने हुए हैं। 2004 में एक बार अजित पवार के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पारिवारिक समीकरणों ने भी शरद पवार और अजित के रिश्ते को और तनावपूर्ण बना दिया। अपने भतीजे को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने के बाद शरद पवार ने 2005 में अपनी बेटी को राजनीति में उतारा। राज्यसभा सदस्य के रूप में सुप्रिया सुले ने शुरू में राज्य की राजनीति से दूरी बनाए रखी लेकिन बाद में अजित के लिए एनसीपी के महाराष्ट्र मामलों में उनके हस्तक्षेप की अनदेखी करना मुश्किल हो गया। अतीत के घटनाक्रम कुछ भी रहे हों लेकिन अब सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। इस पर अभी संशय के बादल हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले विश्लेषक अपना-अपना आकलन कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अजित पवार के निधन के बाद मराठा समुदाय यह सोचेगा कि अब उनके पास कौन है? शरद पवार जीवन के संध्याकाल में हैं और मराठा जाति को यह तय करना है कि उन्हें किस तरफ रुख करना है। राकांपा समय की नजाकत को भांपते हुए एकजुट हो सकती है। मराठा जाति अपनी कमजोर हुई हैसियत को फिर से मजबूत बनाने के प्रयास कर सकती है। दूसरी सम्भावना यह है कि अजित पवार की पार्टी की कमान भले ही उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार या बेटे पार्थ पवार के हाथ में रहे लेकिन पार्टी के कुछ नेता पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। हो सकता है कि पार्टी का देर-सवेर शरद पवार की पार्टी में विलय हो जाए। अजित पवार की पार्टी में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे जैसे अनुभवी नेता तो जरूर हैं लेकिन अजित पवार की राजनीतिक विरासत को सम्भालना किसी के लिए भी सरल नहीं होगा। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में अजित पवार और शरद काफी नजदीक नजर आए और जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव भी साथ-साथ लड़ने जा रहे थे। ऐसे में दोनों गुट यह चाहेंगे कि पार्टी एकजुट हो जाए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की छवि भी मराठा समुदाय में अच्छी खासी है। जनता के साथ उनका जुड़ाव भी काफी है। इस बात की सम्भावनाएं बन रही हैं कि दोनों गुटों में विलय ही अंतिम विकल्प हो सकता है। अजित पवार गुट के पास महाराष्ट्र विधानसभा में 41 विधायक हैं। इसके अलावा पार्टी का लोकसभा में एक सांसद भी है। एक सम्भावना तो यह भी है कि अजित पवार की पत्नी या उनके बेटों पार्थ और जय पवार को उनकी विरासत सम्भालने के लिए आगे लाया जाए। हालांकि पार्थ पवार पहले चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद से ही वे महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। ऐसे में उनमें अपने पिता जैसी राजनीतिक कुशलता और जमीनी पकड़ जैसे कौशल को लेकर अभी बहुत सारे सवाल सामने हैं। दूसरी तरफ शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले उनकी विरासत की उत्तराधिकारी हैं, जबकि रोहित पवार उभरते सितारे के तौर पर देखे जाते हैं। शरद गुट के लिए भी राकांपा पर नियंत्रण और अजित पवार के बराबर का नेता ढूंढना मुश्किल होगा। अजित पवार के बिना उनके गुट के विधायकों की स्थिति कमजोर हो सकती है। बिना किसी मजबूत नेतृत्व के इन विधायकों पर शरद पवार के गुट में वापस लौटने का राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। अगर अजित गुट सरकार से अलग भी होता है तो भी महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भले ही उनकी सरकार स्थिर रहे लेकिन मराठा सियासत का उभार हो सकता है। जनता की सहानुभूति भी पवार परिवार के साथ होगी। इससे भाजपा को आघात लग सकता है। जोड़तोड़ की राजनीति में कोई अंतिम वाकया नहीं लिखा जा सकता लेकिन इतना स्पष्ट है कि अजित पवार के निधन से जो राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई करना अभी मुश्किल होगा।

महाराष्ट्र में 6 बार उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार के राज्य में राजनीतिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अजित पवार जनता के नेता थे और जमीनी स्तर पर लोगों से उनका गहरा जुड़ाव था। उन्हें पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के वंचित वर्ग को सशक्त बनाने और समाज में हाशिये पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों के लिए याद किया जाता रहेगा। राजनीति तो दांव-पेंचों का ही खेल है और महाराष्ट्र की मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों में दांव-पेच कोई नई बात नहीं है। अजित पवार को महाराष्ट्र की सियासत में अपनी कलाबाजियों के लिए भी माहिर माना जाता था। उन्होंने अपने चाचा और दिग्गज मराठा नेता शरद पवार से ही सियासत के गुर सीखे। शरद पवार को वह अपना राजनीतिक गुरु कहते रहे लेकिन 2023 आने तक उन्होंने ऐसा दांव खेला कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने भाजपा को समर्थन दिया और स्वयं उपमुख्यमंत्री बन गए। वह पार्टी का चुनाव चिन्ह भी ले जाने में सफल रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे चाचा शरद पवार की छत्रछाया में 7 बार विधायक चुने गए। अलग राह चुनने के बावजूद चाचा शरद पवार के परिवार से उनके संबंध करीबी बने रहे।

बंद गला को टाटा बाय

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बंद गला पोशाक को समाप्त करने और रेलवे कर्मचारियों की पारंपरिक वर्दी में बदलाव की मंशा जाहिर करने के बाद विवाद तेज हो गया। इसकी मुख्य वजह यह रही कि वैष्णव ने बंद गले को 'औपनिवेशिक हैंगओवर' का प्रतीक बताया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा, हमें औपनिवेशिकता के हर निशान को पहचान कर समाप्त करना होगा। रेलवे में जो बंद गले का काला सूट प्रचलन में है, वह अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। आज से यह रेलवे की औपचारिक वर्दी नहीं रहेगा। स्पष्ट है कि अंग्रेजों के दौर में शुरू किए गए काले प्रिंस कोट को अब रेलवे की औपचारिक पोशाक से बाहर किया जा रहा है। हालांकि इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी कहते हैं। बंद गला पोशाक का संबंध लंबे समय से राजसी परंपराओं से रहा है और इसे राजपूत शासकों तथा जोधपुर के महाराजाओं द्वारा पहना जाता था। ऐसे में जब भारत सरकार ने इसे औपनिवेशिक करार दिया तो भारतीय फैशन डिजाइनरों ने इस दावे को तुरंत चुनौती दी। प्रसिद्ध डिजाइनर राघवेंद्र राठौर का कहना है, यह कहना सरासर अनुचित है कि यह जैकेट हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है या किसी दूसरी संस्कृति की देन है। उनके अनुसार यह परिधान चार शताब्दियों में विकसित हुआ है और कलकत्ता में अंग्रेजों के आने से बहुत पहले से अस्तित्व में था। रिकॉर्ड के लिए यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार यह कह चुके हैं कि विकसित भारत का अर्थ औपनिवेशिक मानसिकता के हर अवशेष को समाप्त करना है। यह केवल बयानबाज़ी नहीं रही, बल्कि ठोस कदमों के जरिये इसे अमल में भी लाया गया है। उदाहरण के तौर पर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाना, अधिकार से अधिक कर्तव्य को प्राथमिकता देने का संकेत। भारतीय नौसेना के ध्वज में औपनिवेशिक सेंट जॉर्ज क्रॉस की जगह तिरंगे से प्रेरित नए प्रतीक को शामिल करना, बीटिंग रिट्रीट समारोह में सितार, तबला और संतूर जैसे भारतीय वाद्ययंत्रों को स्थान देना तथा औपनिवेशिक बजटीय परंपरा के तहत प्रयुक्त ब्रीफकेस को हटाकर पारंपरिक बही-खाता अपनाना, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारतीय होने के गर्व के साथ प्रस्तुत किया। इसी दिशा में एक और कदम रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय करना भी रहा। ऐसे उदाहरणों की सूची लंबी है और यह प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि रिपोर्टों पर भरोसा किया जाए तो मोदी सरकार ने मंत्रालयों और भाजपा-शासित राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे औपनिवेशिक प्रथाओं की पहचान कर उन्हें समाप्त करें और उनके स्थान पर भारतीय विकल्प अपनाएं। अपुष्ट खबरों के अनुसार, सरकार भारतीय अदालतों में वकीलों द्वारा पहने जाने वाले काले कोट और गाउन, जो ब्रिटिश काल की विरासत हैं और जिनमें सफेद नेकबैंड अनिवार्य होता है, उसे बदलने पर भी विचार कर रही है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के दौरान पहने जाने वाले गाउन और टोपी को लेकर भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। बेशक, शहरों, योजनाओं, रेलवे स्टेशनों और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम बदलने को लेकर मोदी सरकार की सक्रियता अपने-आप में एक अलग कहानी है। एक समय पर सरकार ने देश का नाम 'इंडिया' से बदलकर 'भारत' करने की कोशिश भी की थी। इसी संदर्भ में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भेजे गए रात्रिभोज आमंत्रणों में द्रौपदी मुर्मु को 'भारत की राष्ट्रपति' के रूप में संबोधित किया जाना याद किया जाता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने इस कदम की कड़ी आलोचना की लेकिन सरकार उस भव्य और सफल शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद निश्चिंत दिखाई दी। लेकिन बंद गले पर लौटें तो यह निस्संदेह एक तरह की 'सेलिब्रिटी पोशाक' रही है, जिसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे फिल्मी सितारों ने पहना है और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी इसे धारण करते रहे हैं। विदेश दौरों के दौरान बंद गला उनकी 'वार्डरोब स्टेपल' रहा है, यदि इस शब्द का प्रयोग किया जाए। निष्पक्षता के तकाजे के तहत यह भी कहना होगा कि इस बदलाव की पहल करने वाले वैष्णव पहले व्यक्ति नहीं हैं।

लगभग तीन वर्ष पहले भारतीय संसद ने भी बंदगले को अलविदा कह दिया था, जब वहां के सचिवालय कर्मचारियों ने प्रिंस कोट (जिसे बंदगला भी कहा जाता है) की जगह नेहरू जैकेट पहननी शुरू की। संसद के मार्शलों को भी उस समय सफारी सूट की जगह कुर्ता-पायजामा और मणिपुरी पगड़ी में देखा गया, जो मोदी सरकार द्वारा ड्रेस कोड बदले जाने के बाद लागू किया गया था। क्या इस कथित अव्यवस्था के पीछे कोई सुविचारित रणनीति है? निस्संदेह है, क्योंकि 'भारतीयता' अब नया मानक बन चुकी है। 'भारत से प्रेम करो, भारतीय बनो' जैसे भाववाक्य, एक अर्थ में महात्मा गांधी के स्वदेशी मॉडल के पुनरुत्थान का संकेत देते हैं। मोदी सरकार की आलोचना चाहे जितनी की जाए, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने आम नागरिक की चेतना में भारत और भारतीयता के भाव को गहराई से स्थापित करने का प्रयास किया है और यह प्रयास अभूतपूर्व रूप से जनमानस में अपनी जगह बना चुका है। इसी संदर्भ में हर वर्ष 15 अगस्त के आसपास आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा या तिरंगा अभियान को भुलाया नहीं जा सकता। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद को उसके चरम पर प्रदर्शित करना। सड़कों पर दौड़ते ऑटो और निजी वाहन तिरंगे से सजे दिखाई देते हैं, दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज की कमी हो जाती है, क्योंकि उसे खरीदने की होड़ मच जाती है। इस प्रकार मोदी और उनकी सरकार अकेले नहीं हैं, देश स्वयं इस भावना और राष्ट्र के प्रति अपने जज्बे सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना आता है। एक तरह से, उनकी सरकार ने भारतीय समाज में अब तक सुप्त पड़े राष्ट्रवादी भाव को पुनर्जीवित करने में सफलता हासिल की है। इसलिए जब वैष्णव भारतीय रूप वाली वर्दी की पैरवी कर रहे हैं तो वे अकेले नहीं हैं। हालांकि, उनके और उनके सहयोगियों के लिए यह अधिक उपयुक्त होगा कि वे बंदगले पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सेवाओं में ठोस और परिणामोन्मुख सुधारों पर जोर दें। कहने का आशय यह है कि प्रतीकों से पहले प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पॉकेट [illegible], दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के अन्तर्गत निकली रैली

मुरादाबाद।

23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद व स्वास्थ्य विभाग मुरादाबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत अभियान के अंतर्गत स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के अवसर पर एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह एवं मेजर राजीव ढल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली सीएमओ कार्यालय से प्रारंभ होकर सिविल लाइन थाना, जिला अस्पताल, पीली कोठी, जैन मंदिर, डॉ भीमराव अंबेडकर पार्क से होती हुई पुनः सीएमओ कार्यालय पर समाप्त हुई। इस रैली के दौरान 23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद की सब यूनिट महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट नारे लगाते हुए चल रहे थे एनसीसी कैडेटों ने ठाना है कुष्ठ मुक्त भारत बनाना है, महात्मा गांधी का एक ही सपना कुष्ठ मुक्त हो भारत अपना । रैली के दौरान सड़क पर चल रहे लोगों ने एनसीसी कैडेटों का तालियां बजाकर अभिवादन किया और उनका हौसला अफजाई की रैली की समाप्ति पर एनसीसी कैडेटों को मेजर राजीव ढल और डॉ कुलदीप सिंह ने कुष्ठ रोग निवारण अभियान में सहयोग करने की शपथ भी दिलाई। डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया

कि यह जन जागरूकता अभियान आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलाया जाएगा और लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर मेजर राजीव ढल ने कहा कि कुष्ठ रोग साध्य है इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है इसके लक्षणों पर यदि हम ध्यान दें तो अति शीघ्र इसका इलाज किया जा सकता है लोगों में कुष्ठ रोग के प्रति विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियां को दूर करने के लिए हमारे एनसीसी कैडेट जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और स्वयं तो प्रेरित हो ही रहे हैं साथ-साथ दूसरों को भी इस कुष्ठ रोग निवारण के प्रति जागरूक करेंगइस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. कुलदीप सिंह ने जिलाधिकारी का संदेश पढ़कर सुनाया। डॉ रामानंद बाजपेई ने कुष्ठ रोग के कारण और उनके उपचार के बारे में जानकारी दी।

डॉ भास्कर अग्रवाल ने कुष्ठ रोग निवारण के संबंध में किए जा रहे सरकार एवं स्वास्थ विभाग के प्रयासों के बारे में जानकारी दी और बताया कि यह ला इलाज बीमारी नहीं है दवाइयां के सेवन से इसे समाप्त किया जा सकता है।

इस मौके पर डॉ कुलदीप सिंह सीएमओ, मेजर राजीव ढल, डॉ. भास्कर अग्रवाल जिला कुष्ठ परामर्श दाता मुरादाबाद जिला नाभिक टीम के डॉ रामानंद बाजपेई जी फिजियोथैरेपिस्ट डॉ नितिन यादव, राहुल भटनागर, संजीव कुमार, रघुवीर सिंह, विशेष कुमार, अमित कुमार,मोहम्मद फैजान, शिवा, गुलफशा, सुखवीर सिंह, तसुबूर हुसैन, सुमित कुमार, कृष्णा विकास, सहित बड़ी संख्या एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे।

स्टुडेंट्स को समझाया खेल चोटों का प्रबंधन

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से आईआईसी के तत्वावधान में क्रिकेट में उन्नत बायोमैकेनिकल मूल्यांकन तकनीकों पर कार्यशाला में विशेष रूप से क्रिकेट खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स फील्ड पर खेल चोटों के प्रबंधन और गति तंत्र विश्लेषण की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। मुजफ्फरनगर की जानी-मानी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. शिवानी लाल ने सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग से जोड़ा। यूपीसीए की अंडर-19 टीम की चयनित महिला क्रिकेटर्स- मनीषा चौधरी, शुभ चौधरी और पलक पर डॉ. लाल ने व्यावहारिक बायोमैकेनिकल का डेमो दिया। उन्होंने वास्तविक समय में मूल्यांकन तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ियों के गति पैटर्न और चोट के जोखिम कारकों पर व्यक्तिगत फीडबैक प्रदान किया। इससे पूर्व स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. लाल ने विभागाध्यक्ष डॉ. शिवानी एम. कौल के संग दीप प्रज्वलित करके वर्कशॉप का शुभारम्भ किया। वक्ताओं ने खेल फिजियोथेरेपी के महत्व और इस कार्यशाला की प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रश्नोत्तर सत्र में छात्रों ने खेल बायोमैकेनिक्स और चोट की रोकथाम के विभिन्न पहलुओं पर सवाल पूछे। डॉ. लाल ने स्टुडेंट्स की जिज्ञासा को शांत किया। अंत में डॉ. शिवानी लाल को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हरीश शर्मा, हिमानी, डॉ. कंचन खोलिया, समर्पिता सेनापति, शिप्रा गंगवार, सिमरन सरफराज के संग-संग फिजियोथेरेपी के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

टीएमयू की क्रिकेट बायोमैकेनिक्स में वर्कशॉप

कलश यात्रा से हुआ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ का शुभारम्भ

मुरादाबाद।

श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति (रजि0) मुरादाबाद एवं श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट मुरादाबाद के तत्वावधान में आयोजित पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री शिव कथा महोत्सव का शुभारम्भ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर भक्ति भाव से यात्रा में सहभागिता की। जयकारों, मंत्रो'चार एवं भजनों से क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। पंडित कृष्ण स्वामी जी द्वारा यज्ञ का आरम्भ कराया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिन शोभा यात्रा के उपरांत आशीष माधव के द्वारा शिव कथा प्रारम्भ की

गयी कथा व्यास आचार्य आशीष माधव ने भगवान शिव के माहात्म्य का वर्णन किया। व्यास ने कहा कि भगवान शिव की महिमा देश-काल की सीमाओं से परे है। भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में शिव उपासना के साक्ष्य मौजूद हैं। कार्यक्रम मे मुख्य यजमान के रूप मे विनीत लोहिया, महायज्ञ के यजमान के के गुप्ता रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप मे मुरादाबाद महापौर विनोद अग्रवाल, मुख्य रूप से प्रिया अग्रवाल, अनीता श्रीवास्तव, रुपाली अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, वीना अरोड़ा, सुनीता गुप्ता, दिव्य अग्रवाल, धवल दीक्षित, प्रीति कश्यप, रेखा मदान, निरु ग्वाल, सुनीता शर्मा, रुचि चौधरी, कोमल गांधी, अनीता मदान, रुचि मदान, सुमन सक्सैना, राजीव अग्रवाल मल्लू,अवनीत सक्सेना ,के के गुप्ता ,सुधीर श्रीवास्तव, दिनेश अग्रवाल जी ,वरुण सक्सेना ,अतुल सोती ,के ऐ सक्सेना ,अखिलेश सक्सेना ,विकास ममगाईं,अंकित सक्सेना ,सौभाग्य सक्सेना ,शोभित सक्सेना ,मुकेश कौशिक, सुमन सक्सेना ,नीलम अग्रवाल ,अंजू सक्सेना ,छमा अग्रवाल , अनुराधा तोमर ,प्रभा गुप्ता ,अर्चना अग्रवाल, शिला श्रीवास्तव ,उमा तोमर नीलम अग्रवाल, अंजू सक्सैना, छमा अग्रवाल, शीला श्रीवास्तव, उमा तोमर, संगीता मीनू ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे।

आयोजकों ने बताया कि महायज्ञ एवं श्री शिव कथा के माध्यम से क्षेत्र में धार्मिक चेतना, सकारात्मक ऊर्जा एवं सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम के आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान एवं कथा आयोजन संपन्न होंगे। संचालन राजीव अग्रवाल मल्लू एव अवनीत सक्सेना ने किया ।

कम्युनिस्ट बोले, देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को समाप्त करना चाहती है सरकार

पुण्य तिथि पर गांधी जी को किया नमन

मुरादाबाद। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तत्वावधान में आज महात्मा गांधी की शहादत पर कचहरी में बलिदान दिवस के नाम से एक शोक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड जयप्रकाश शर्मा ने की और संचालन शरीफ अहमद ने किया। शोक सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव कामरेड थानसिंह ने कहा कि वर्तमान सत्ताधारियों के निशाने पर आज महात्मा गांधी, नेहरू और अम्बेडकर हैं। सरदार पटेल को अपनाकर और नेहरू को नजरंदाज करके वह देश के साप्रदायिक सदभाव को नष्ट करना चाहते हैं, और अपने साम्रा'यवादी आकाओं को खुश करने के लिए देश की आजादी के बाद स्थापित धर्मनिरपेक्ष ढांचे को समाप्त कर देना चाहते हैं। जिसकी हिफाजत के लिए महात्मा गांधी को याद किया जाना प्रासंगिक होगा। शोक सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड विक्रम सिंह एडवोकेट एवं पार्टी जिला कमेटी सदस्य कामरेड एच एन मिश्रा ने कहा कि गांधी आजाद भारत के आदर्श हैं, जिन्होंने समाजवाद और भाईचारे को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि वर्तमान सरकार महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमामंडित कर रही है। इस अवसर पर ओम प्रकाश सैनी, महिपाल सिंह, अर्जुन सिंह सेनी, खान असलम जावेद, ताहिर अली खान, अहमद हसन अंसारी, नीतेश सिंह एडवोकेट, संजीव कुमार एवं सुशील विश्नोई ने भी विचार व्यक्त किए। शोकसभा में दो मिनट का मौन धारण करके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

बेहद फजीलत वाली रात है शबे बारात-अहसन मियां

नौजवान हुड़दंग,शोर-शराबे से बचते हुए इबादत में गुजारे रात-मुफ्ती सलीम नूरी

बरेली ।

शबे बारात 03 फरवरी मंगलवार को देश भर में मनाई जाएगी। शबे बारात की रात में लोग रात भर जागकर अल्लाह की इबादत करते है। मस्जिदों,कब्रिस्तानों और दरगाहों की साफ-सफाई के साथ रौशनी की जाती है। बुजुर्गों के मजारों पर हाज़िरी देने के साथ कब्रिस्तान में जाकर घर-खानदान से जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए इसाले सवाब करते है। ये सिलसिला रात भर चलता है। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि इस मौके पर दरगाह आला हज़रत के सज्जादा-नशीन बदरूशरिया मुफ़्ती अहसन रज़ा क़ादरी(अहसन मियां) ने आज दरगाह मुख्यालय पर बाद नमाज़-ए-जुमा शबे बारात की फज़ीलत बयान करते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया की जब शाबान की 15 वी शब आये तो कयाम (इबादत)करो और इसके दिन का रोज़ा रखों। यह रात बड़ी फजीलत,रहमत और बरकत वाली रात है। इस दिन मुस्लमान अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें।

ज़िंदगी में जो नमाज़ कज़ा हो गई उसको अदा करे। इसके अलावा नफल नमाज़, रोज़ा ,तस्बीह, अस्तगफार व कुरान की तिलावत करे। ये रात गुनाहों से निजात (छुटकारे) की रात है ये रात उन खास रातों में से एक है जिसमें अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कुबूल करता है। इसलिए मुसलमान अपने रब को राज़ी करने के लिये ज्यादा से ज्यादा इबादत करे। अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने पूर्वज जो इस दुनिया से तशलीफ ले गए उनके लिए खूब इसाले सवाब करें। मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने कहा कि इस दिन बेसहारों, बेवाओं, यतीमों व ज़रूरतमंदों की खूब मदद करें। उनको खाना खिलाए। तमाम बुरे कामों से बचना का इरादा करे। इस रात खासकर नौजवान बाइकों से स्टंट व हुड़दंग हरगिज़ न करें। दरगाह के जिम्मेदार शाहिद खान नूरी,हाजी जावेद खान,अजमल नूरी,औरंगज़ेब नूरी,परवेज़ नूरी,ताहिर अल्वी व मंजूर रज़ा ने नगर निगम से शहर भर की सभी दरगाहों,खानकाहों,मस्जिदों और कब्रिस्तानो के आस पास विशेष सफाई और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। बैठक में मौलाना बशीरूल क़ादरी,मुजाहिद रज़ा, शान रज़ा, इशरत नूरी, आलेनबी, सय्यद माजिद, सय्यद एजाज़, युनुस गद्दी,काशिफ सुब्हानी, अब्दुल माजिद,साजिद नूरी,सुहैल रज़ा, शाद रज़ा,अरवाज रज़ा,अमान रज़ा,हाजी शरिक नूरी,तारिक सईद, शरिक बरकाती,सबलू अल्वी,आरिफ नूरी आदि लोग मौजूद रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजीव साहू बनाये गये जिलाध्यक्ष

जौनपुर।

नगर के जोगियापुर में लोक शक्ति उद्योग व्यापार मण्डल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण जायसवाल की अध्यक्षता में व्यापारियों की आम बैठक बुलाकर जिला कमेटी का घोषणा की गयी। इस मौके पर सर्वसम्मत से जिलाध्यक्ष के रूप में संजीव साहू को मनोनीत किया गया। वहीं जिला महामंत्री शशि श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष देवेन्द्र साहू, जिला कोषाध्यक्ष रंजीत सोनकर, जिला मंत्री गगन जायसवाल का मनोनयन किया गया। बता दें कि संजीव साहू अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों को माल्यार्पण करते हुये प्रदेश अध्यक्ष श्री जायसवाल ने कहा कि आज आप सभी का मनोनयन करते हुये हर्ष हो रहा है कि जो लोग व्यापारी हितों हेतु संघर्ष में सदैव शामिल रहे, उनका पदों पर आसीन करना फक्र की बात है। यह जो पद आप सभी को दिये

व्यापारी हित के लिये सदैव खड़ा रहेगा लोक शक्ति उद्योग व्यापार मण्डल - श्रवण जायसवाल

गये हैं, वह कांटो भरा तक है। आये दिन व्यापारिक समस्याएं आती रहती हैं जिसके लिये आप सभी को उनके हितों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प इस बात का आप सभी को लेना है कि व्यापारी हित सर्वोपरि है और रहेगा। वहीं प्रदेश महामंत्री अनवारूल हक ने कहा कि हमारा व्यापार मण्डल हमारे हमेशा संघर्षों की कहानी लिखता रहा है। आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि इस परम्परा को आगे बढ़ाना है। साथ ही मनोनीत जिलाध्यक्ष संजीव साहू ने कहा कि संगठन का नेतृत्व जो भी आदेश देगा और जहां भी व्यापारियों को आवश्यकता पड़ेगी, वहां हम सभी खड़े मिलेंगे। इस अवसर पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर बहादुर सेठ, प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ मोदनवाल, प्रदेश मंत्री सुनील चौरसिया, राजेश यादव, गणेश साहू, सुभाष गुप्ता, मनोज जायसवाल, भाई जी साहू, पवन जायसवाल, रतन जायसवाल सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे।

मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी के बीच खूनी खेल! चाकू मारकर युवक की हत्या, 1 की हालत गंभीर

नई दिल्ली।

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मामूली कहासुनी के चलते खूनी खेल की घटना सामने आई है. यहां शुक्रवार (30 जनवरी) की सुबह एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से किए गए हमले में एक युवक की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, हालांकि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज दो घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मंगोलपुरी थाना पुलिस को सुबह सूचना मिली कि एक युवक का शव खून से लथपथ हालत में सड़क किनारे फुटपाथ पर पड़ा है. जानकारी मिलते ही मंगोलपुरी थाने के एसएचओ, जिले के डीसीपी, क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल की बारीकी से जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई. हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान संदिग्ध की पहचान हो गई और पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई की. वारदात के महज चंद घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार

भी बरामद कर लिया गया. मृतक की पहचान 28 वर्षीय मोहित के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक मोहित धार्मिक आयोजनों और जागरण में झांकियों के दौरान डांस करने का काम करता था. बीती रात वह दोस्तों के साथ काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था. शुक्रवार (30 जनवरी) की सुबह परिवार को सूचना मिली कि मोहित का शव घर से कुछ दूरी पर पड़ा है, जिसके बाद परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे. मोहित के परिवार का कहना है कि उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा कि उनके बेटे की हत्या क्यों की गई. परिजनों के अनुसार मोहित की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हुई. परिवार का दर्द छलक पड़ा जब उन्होंने कहा कि अगर किसी ने समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया होता, तो शायद आज मोहित जिंदा होता. पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के आरोप में पकड़े गए युवक का नाम तन्नू है, जो मंगोलपुरी के खाई ब्लॉक का रहने वाला है. मृतक और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. बताया जा रहा है कि मोहित अपने दो दोस्तों के साथ आरोपी के पास किसी सामान के सिलसिले में गया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और तन्नू ने मोहित और उसके दोस्त विक्की पर चाकू से हमला कर दिया.

घटना के बाद से पूरे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों का दावा है कि मंगोलपुरी क्षेत्र में पिछले एक महीने के अंदर यह तीसरी हत्या की वारदात है. लोगों का आरोप है कि आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. मंगोलपुरी थाना पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले में जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है. हालांकि दिल्ली में लगातार हो रही हत्याओं ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली।

देश ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता को नमन किया। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। सभी ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और उनके विचारों को याद किया। इस दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

पूय बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूय बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधारस्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने लिखा, पूय बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। इसमें वह शक्ति है, जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है। अहिंसा परमो धर्मस्तथा हिंसा परन्तपः। अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते॥

आरटीआई की हत्या की तैयारी? Economic Survey पर भड़के खड़गे, मोदी सरकार से पूछा तीखा सवाल

नई दिल्ली।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आर्थिक समीक्षा में सूचना का अधिकार अधिनियम का फिर से अध्ययन करने की पैरवी किए जाने का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि क्या सरकार मनरेगा के बाद अब इस कानून को खत्म करना चाहती है? संसद में बृहस्पतिवार को प्रस्तुत वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में लगभग दो दशक पुराने आरटीआई कानून का फिर से अध्ययन करने की वकालत की गई है, ताकि गोपनीय रिपोर्ट और मसौदों को सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त हो। आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया कि आरटीआई अधिनियम 2005 का मकसद कभी भी इसे व्यर्थ की जिज्ञासा का जरिया बनाने का नहीं था, न ही इसका मकसद बाहर से बैठकर सरकार के हर छोटे-छोटे काम में दखल देना या उसे नियंत्रित करना था। खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, आर्थिक समीक्षा ने सूचना का अधिकार अधिनियम को फिर से अध्ययन करने की पैरवी की है। यह

सूचना को रोकने के लिए संभावित मंत्री स्तरीय बोटो का सुझाव भी देती है और यह देखने की बात करती है कि क्या नौकरशाहों को सार्वजनिक सेवा से जुड़े रिकॉर्ड, तबादले और स्टाफ रिपोर्ट्स को सार्वजनिक निगरानी से बाहर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से आरटीआई अधिनियम को कमजोर किया है। 2025 तक 26,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। 2019 में मोदी सरकार ने आरटीआई अधिनियम में कटौती करते हुए सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जिससे स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं को आज्ञाकारी अफसरों में बदल दिया गया। खरगे ने आरोप लगाया कि डिजिटल डेटा सुरक्षा अधिनियम, 2023 की आड़ में जनहित वाले प्रावधान को खोखला कर दिया गया तथा निजता को हथियार बनाकर भ्रष्टाचार को ढकने और जांच-पड़ताल रोकने का रास्ता खोल दिया गया। उन्होंने कहा, दिसंबर, 2025 तक केंद्रीय सूचना आयोग बिना मुख्य सूचना आयुक्त के काम कर रहा था, 11 साल में सातवीं बार इस अहम पद को जानबूझकर खाली रखा गया। 2014 से अब तक 100 से ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जिससे सच बोलने वालों को दबाने और असहमति की आवाज दबाने का माहौल बना है। खरगे ने सवाल किया, मनरेगा को खत्म करने के बाद, क्या अब आरटीआई की बारी है?

लखनऊ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 275 यात्री थे सवार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट से सऊदी अरब जा रहे एक विमान की शुक्रवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उड़ान के कुछ समय बाद विमान में तकनीकी दिक्कत आ गई थी। सूत्रों के मुताबिक, जब विमान मुंबई के पास पहुंचा, तब केबिन प्रेशर में समस्या आ गई। इसके चलते कुछ यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। हालात देखते हुए पायलट ने पहले मुंबई एयरपोर्ट से संपर्क कर लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन वहां से परमिशन नहीं मिली। इसके बाद पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट से संपर्क किया। लखनऊ से इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मिलते ही विमान वापस लौट आया। करीब 82 मिनट में विमान सुरक्षित रूप से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा। खराबी दूर होने पर विमान जेद्दा के लिए रवाना हो गया।

गांधीवादी विचारधारा से ही नकारात्मक, हिंसक ताकतों को हराया जा सकता है : अखिलेश यादव

लखनऊ । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए कहा कि गांधीवादी विचारधारा को सक्रिय करने से ही नकारात्मक-हिंसक ताकतों को हराया जा सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन! इसी पोस्ट में उन्होंने आगे कहा गांधी जी के सत्य पर अडिग विश्वास; मानवता के स्नेह सूत्र सहिष्णुता, अहिंसा, दया, करुणा और सौहार्द के सिद्धांतोंवाली अमर गांधीवादी विचारधारा से ही उन नकारात्मक-हिंसक ताकतों को बेनकाब और परास्त किया जा सकता है जो अभी भी नये मुखौटे लगाकर हमारे देश और समाज के लिए घातक बनी हुई हैं। महात्मा गांधी की 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

बापू एक व्यक्ति नहीं सोच हैं, अहंकारी सत्ता ने इसे मिटाने की असफल कोशिश की- राहुल गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और कहा कि बापू एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सोच हैं जो कभी मिट नहीं सकती क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस सोच को कभी अंग्रेजी साम्राज्य ने, कभी नफरत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया, महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच हैं वह सोच जिसे कभी एक साम्राज्य ने, कभी नफरत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की। मगर राष्ट्रपिता ने हमें आजादी के साथ यह मूलमंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है - और हिंसा व भय से बड़े अहिंसा और साहस।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सोच मिट नहीं सकती, क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर हैं। राहुल गांधी ने कहा, बापू को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरदार वल्लभभाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच 1948 में हुए पत्राचार का उल्लेख करते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, महात्मा गांधी की हत्या से दो दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा था। कुछ महीनों बाद, 18 जुलाई 1948 को, सरदार पटेल ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, इन दोनों पत्रों में स्वयं को राष्ट्रहित का स्वयंभित संरक्षक बताने वालों पर बेहद गंभीर आरोप हैं। यह सोचकर हैरानी होती है कि उसी विचारधारा से जुड़े एक लोकसभा सदस्य (अभिजीत गंगोपाध्याय), जिन्हें स्वयं प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है, ने यह कहा कि वह गांधी और गोडसे के बीच चयन नहीं कर सकते। उनकी यह मानसिकता बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्र के नाम संबोधन से जुड़ा एक लिंक भी साझा किया। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी, 1948 को नयी दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी।

राहुल गांधी ने किया पूर्वोत्तर का अपमान, गमोसा ना पहनने पर कांग्रेस पर बरसे अमित शाह

नई दिल्ली। असम की पारंपरिक पोशाक गमछा को लेकर एक कार्यक्रम में राहुल गांधी की मौजूदगी पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर असम और पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा दिए गए गमछे को पहनने से इनकार किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कुछ भी करें, लेकिन जब तक भाजपा सत्ता में है असम की संस्कृति का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। शाह ने यह बयान असम के डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों, यहां तक कि विदेशी मेहमानों ने भी सम्मान के तौर पर गमछा पहना लेकिन राहुल गांधी ने नहीं पहना। यह

बयान ऐसे समय में आया है जब असम में इस साल चुनाव होने वाले हैं, जिससे इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को असम और पूर्वोत्तर की संस्कृति का सम्मान करना सिखना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी लोगों की संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते, तो उन्हें उनसे वोट भी नहीं मांगना चाहिए। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों का हवाला देते हुए दावा किया कि राहुल गांधी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गमछा नहीं पहना।

कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए गलत प्रचार कर रही है। खरगे ने कहा, राहुल गांधी अकेले नहीं थे जिन्होंने गमछा नहीं पहना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने भी गमछा नहीं पहने थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी गमछा हाथ में लिए हुए थे और बाद में पहन भी लिया था। मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे को पलटते हुए सरकार पर खुद राहुल गांधी का अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर उन्हें और राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बैठाया गया था।

राजकोट में कार पुल से गिरी, आग लगने के बाद तीन की मौत

नई दिल्ली। गुजरात के राजकोट जिले में आज शुक्रवार, 30 जनवरी की सुबह एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें एक कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई। कार पुल की दीवार से टकराकर नीचे गिरी, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। इस कार में दो महिला शिक्षक समेत तीन लोग सवार थे, जिनकी आग में झुलसकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया, यह हादसा गोंडल-अटकोट हाईवे पर सुबह करीब 5.30 बजे हुआ, जब कार छोटा उदयपुर से गोंडल की ओर जा रही थी। पुलिस उपाधीक्षक नवीन चक्रवर्ती ने बताया, कार एक छोटी नदी पर बने 8 फुट ऊंचे पुल की साइड की दीवार से टकराई और दीवार तोड़कर नीचे गिर गई। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, गड्ढे के नीचे गिरने के तुरंत बाद उसमें आग लग गई, जिससे उसमें सवार लोग अंदर फंस गए, जिससे तीनों यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।

अजित पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने की मांग, एनसीपी नेता फडणवीस से मिले, विभाग भी मांगे

मुंबई । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेताओं ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और पार्टी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विभागों पर अपना दावा जताया। अजीत पवार का बुधवार को विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल प्रमुख कैबिनेट पदों पर पार्टी का नियंत्रण बरकरार रखने के लिए फडणवीस के वर्षा बंगले पर पहुंचे। प्रफुल पटेल ने कहा कि हम पवार परिवार से बात करने के बाद और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही फैसला लेंगे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पटेल ने कहा कि पार्टी इस पद को जल्द से जल्द भरना चाहती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी निर्णय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम महायुति गठबंधन के साझेदार हैं, इसलिए अजित पवार के पद को भरने के लिए हमें जल्द से जल्द सही निर्णय लेना होगा। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें जनभावना का ध्यान रखना होगा। हमें परिवार को उनके दुख से उबरने के लिए कुछ समय देना चाहिए। हम जल्द ही सुनेत्रा पवार और परिवार के साथ पार्टी के भविष्य के मार्ग पर चर्चा करेंगे। अजित पवार के अचानक निधन ने एनसीपी के भीतर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे शरद पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट के साथ विलय की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। इससे पार्टी के भावी नेतृत्व को लेकर भी अनिश्चितता का माहौल बन गया है, क्योंकि अजीत पवार के निधन से एक बड़ा रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया है। एनसीपी ने रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जहां अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। एनसीपी सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें भाजपा और शिवसेना भी शामिल हैं। शनिवार की बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव भी होने की उम्मीद है।

योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें- अविमुक्तेश्वरानंद

काशी।

ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि योगी सरकार को गोमाता की रक्षा के लिए अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए 40 दिनों का समय दिया जा रहा है। यदि इस अवधि में गोमाता को राज्यमाता का दर्जा नहीं दिया गया और गोवंश निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो परिणाम गंभीर होंगे। शंकराचार्य ने कहा, जो सरकार गोवंश की रक्षा नहीं कर सकती, उसे हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विशेष रूप से उस योगी को तो बिल्कुल नहीं, जो गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र गद्दी का महंत होने का दावा करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा, हमसे आपने हमारा प्रमाण-पत्र मांग लिया था, हमने सहज भाव से दे दिया, क्योंकि सत्य को प्रमाण से भय नहीं होता। अब समय आपके हिंदू होने का प्रमाण देने का है। सनातनी समाज अब आपसे आपके हिंदू होने

का साक्ष्य मांगता है। हिंदू होना केवल भाषणों या भगवा वस्त्र तक सीमित नहीं है, इसकी कसौटी गो-सेवा और धर्म-रक्षा है। शंकराचार्य ने दो स्पष्ट शर्तें रखीं- गोमाता को राज्यमाता का आधिकारिक दर्जा दिया जाए, जैसा महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में देशी गायों के लिए किया है और नेपाल में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा गोवंश निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का शासनादेश जारी किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी, यदि 40 दिनों में ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 10-11 मार्च को लखनऊ की पावन धरा पर संपूर्ण संत समाज का समागम होगा। उसमें सरकार को नकली हिंदू और छद्म हिंदू घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कालनेमी भी घोषित किया जाएगा। शंकराचार्य ने आगे कहा कि स्वतंत्र भारत में गोमाता की रक्षा और गोहत्या बंदी की मांग करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। जब-जब इस मुद्दे पर आवाज उठी, सरकारों ने उसे क्रूरता से कुचल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि को धूमिल करने के प्रयास हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अपने विश्वस्तों (जैसे रामभद्राचार्य) के माध्यम से इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तराखंड ने राज्यमाता का प्रस्ताव दिया, महाराष्ट्र ने राज्यमाता बनाया, तो भगवान राम और कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश मांस निर्यात का केंद्र क्यों बना हुआ है? यह केवल पद की लड़ाई नहीं, बल्कि सनातन की आत्मा की रक्षा का प्रश्न है।

- **गाय को गोमाता घोषित करें, वरना मानेंगे सिर्फ दिखावे के लिए भगवा पहना**
- **गोमाता को राज्यमाता दर्जा और गोवंश निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग, 40 दिन का अल्टीमेटम**

यूजीसी के बहाने बढ़त लेने के मूड में सपा-बसपा

नई दिल्ली ।

यूजीसी ने जहां भाजपा के चुनावी समीकरण गड़बड़ कर दिए हैं, वहीं सपा-बसपा दोनों ही इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं। सपा-बसपा दोनों ही पार्टियों की नजर इस बार ब्राह्मण सहित सामान्य वोट बैंक पर है जो यूजीसी के कारण भाजपा से नाराज चल रहा है। सपा का आकलन है कि यदि सामान्य वर्ग का एक हिस्सा वोट भी उसके साथ वापस आ जाता है तो विधानसभा चुनाव में वह बढ़त हासिल कर सकती है। वहीं, प्रदेश में अपनी मजबूत वापसी के लिए कोशिश कर रही बसपा एक बार फिर ब्राह्मणों को साधकर 2007 का करिश्मा दोहराना चाहती है। समाजवादी पार्टी इस समय हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को आगे रखकर प्रदेश के ब्राह्मणों के बीच छोटी-छोटी बैठक कराकर अपने से जोड़ने की कोशिश कर रही है। माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाकर भी उसने ब्राह्मणों को एक संदेश देने का काम किया है। अखिलेश यादव ने यूजीसी विवाद के बाद जिस तरह किसी के साथ भी अन्याय न होने की बात कही है, उसे ब्राह्मणों सहित अन्य सामान्य वर्ग को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

ये इतिहास सपा के साथ

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने अमर उजाला से कहा कि यूपी का अब तक का इतिहास रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल करता है, प्रदेश में उसकी सरकार बनती है। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी, उसे 2017 में यूपी में सरकार बनाने का अवसर मिला। उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बढ़त हासिल की और 2022 में भी सरकार बनाई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को झटका लगा, जबकि समाजवादी पार्टी ने शानदार बढ़त हासिल की। सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी की 43 सीटों पर जीत हासिल की। विधानसभा वार इस परिणाम का आकलन करें तो समाजवादी पार्टी को 235 विधानसभा सीटों पर साफ बढ़त

ज्ञान - विज्ञानं विमुक्तये

मिलती हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि सपा अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए पीडीए वर्ग के साथ-साथ ब्राह्मणों और अन्य सामान्य वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। आईपी सिंह का दावा है कि इस बार समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रहेगी। समाजवादी पार्टी का अनुमान है कि यूजीसी विवाद के साथ-साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद से भी उसको लाभ हो सकता है।

बसपा को अपनी मजबूत वापसी का भरोसा

मायावती यूपी में एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी होने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। बसपा का अनुमान है कि यूजीसी विवाद बढ़ने पर ब्राह्मण मतदाता भाजपा से दूर छिटकते हैं तो वे उसके पास आ सकते हैं और उसके लिए 2007 का सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में बसपा ने एक बार फिर ब्राह्मणों को साधने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। यूजीसी विवाद ने पार्टी को नई उम्मीद देने का काम किया है। बसपा प्रवक्ता फैजान खान ने अमर उजाला से कहा कि उनकी नेता मायावती ने साफ कह दिया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर यह निर्णय किया गया होता तो आज यह तनाव की स्थिति पैदा न होती। उन्होंने कहा कि विभिन्न समाजों के बीच जो तनावपूर्ण माहौल बन रहा है, उसे हर हालत में टालने की कोशिश की जानी चाहिए। फैजान खान ने दावा किया कि उनकी नेता मायावती के नेतृत्व में हर वर्ग को न्याय सुनिश्चित होगा।

जानबूझकर संघर्ष बढ़ाने की कोशिश कर रहे भाजपा- अजय कुमार लल्लू

उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर एक संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहती है जिससे लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए। उन्होंने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ओबीसी समुदाय की ज्यादा भागीदारी देने की बात करते हैं। उन्होंने ही जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाकर भाजपा को इस मुद्दे पर सामने आने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन भाजपा ओबीसी समुदाय को कुछ देना नहीं चाहती, लिहाजा वह लोगों के बीच तनाव बढ़ाकर कुछ करने से बचने की कोशिश कर रही है। अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ओबीसी समुदाय को जो अधिकार दिए हैं, भाजपा उसे उन्हें नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर मुखर रहेगी और ओबीसी समुदाय का हित सुरक्षित करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार - भाजपा

भाजपा अभी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचने की कोशिश कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को कहा कि यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है। ऐसे में पार्टी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी।